



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2700 /2026

वर्षा

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता	:	दिलीप कुमार पांडे, सौरभ पांडे
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	जी.ए., मेधा, विजय शांतम

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ पांडे, सूचना देने वाले के अधिवक्ता श्री विजय शांतम और राज्य के अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 485/2025, धारा 103(1), 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- डिबाई, जिला-बुलंदशहर के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम घटना के तीन महीने बाद 11.10.2025 को सूचना देने वाले के दिए गए एक आवेदन में आया है, जिसमें उसने कहा है कि आवेदक ने अपने प्रेमी गौरव के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मिलकर हत्या का यह अपराध किया था क्योंकि आवेदक का मकसद यह था कि वह अपनी छोटी बहन की शादी मृतक व्यक्ति से करना चाहती थी।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि 11.10.2025 की यह आवेदन धारा 181 बीएनएसएस के तहत आती है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह आवेदन बाद में सोची गई थी। आवेदक के खिलाफ कोई ठोस या सीधा सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि आवेदक ने मृतक व्यक्ति के ससुराल वालों को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 23.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।

6. इसके उलट, आवेदक के अधिवक्ता और ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का इस आधार पर जोरदार विरोध किया है कि आवेदक की मिलीभगत इस बात से साफ़ है कि उसकी सह-आरोपी गौरव से नियमित बातचीत होती थी। ये बातचीत 34 बार हुई और आवेदक और गौरव के मोबाइल की स्थान घटनास्थल के पास मिली है। टावर के स्थान से पता चलता है कि वे दोनों घटनास्थल के आस-पास ही थे।

7. "जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक बेगुनाही का अंदाज़ा" का प्रसिद्ध सिद्धांत, नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल के अवधारणा को जन्म देता है।

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी सिर्फ़ इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि उस व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि अपराध साबित होने में कोई शक न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया सही और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।

9. ऊपर कही गई बात को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह बहुत अच्छी तरह से तय सिद्धांत कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे नहीं भूलना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मानें कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

10. विद्वान ए.जी.ए. ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं बता सके जिससे आवेदक को जमानत देने से मना किया जा सके।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम घटना के तीन महीने बाद आया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्ज़ी **मंजूर** की जाती है।

12. आवेदक- **वर्षा**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

(iv) आवेदक हर महीने के पहले सोमवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेगा।

13. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

14. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।